



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]  
No. 388]नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 12, 2010/आषाढ़ 21, 1932  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 12, 2010/ASADHA 21, 1932

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 595(अ).—केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) की धारा 36 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 15 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया), नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होने का विस्तार.—ये नियम अधिनियम के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण के प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को लागू होंगे।

3. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “अधिनियम” से बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) अभिप्रेत है;

(ख) “न्यायाधीश” से नियम 5 के उप-नियम (2) के अधीन जांच करने के लिए नियुक्त उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश अभिप्रेत है;

(ग) “पीठासीन अधिकारी” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(घ) “अधिकरण” से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

4. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति.—(1) यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई लिखित शिकायत प्राप्त की जाती है जिसमें किसी पीठासीन अधिकारी के संबंध में कदाचार या अपने पद के कृत्यों का पालन करने में असमर्थता के निश्चित आरोप अभिकथित किए गए हैं तो वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक छानबीन करेगी।

(2) यदि, प्रारंभिक छानबीन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अभिकथन का अन्वेषण करना आवश्यक समझती है तो वह उस शिकायत को, उपलब्ध अन्य समर्थक सामग्री सहित शिकायत में किए गए अभिकथनों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए समिति के समक्ष रखेगी जिसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(i) सचिव (समन्वय और लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय —अध्यक्ष

(ii) सचिव, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग —सदस्य

(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय —सदस्य

(3) समिति अन्वेषण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया और पद्धति खोजेगी जिसमें परिवादी का साक्ष्य अभिलिखित करना और

इन नियमें के अधीन उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा की जाने वाली जांच से सुसंगत सामग्री का संग्रहण भी सम्मिलित है।

(4) समिति अपने निष्कर्ष राष्ट्रपति को, यथासंभव शीघ्र, राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

5. न्यायाधीश का जांच करना.—(1) यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि किसी पीठासीन अधिकारी पर कदाचार या असमर्थता के किसी अभ्यारोपण की सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं तो वह, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को एक निर्देश करेंगे जिसमें यह अनुरोध होगा कि जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा जांच करने के प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे।

(3) उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित पीठासीन अधिकारी को दी जाएगी।

(4) राष्ट्रपति, निम्नलिखित की एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेंगे—

- (क) संबंधित पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध आरोप की मद्दें और अभ्यारोपण का कथन;
- (ख) साक्षियों का कथन, यदि कोई हो; और
- (ग) जांच से सुसंगत तात्त्विक दस्तावेज।

(5) उप-नियम (2) के अधीन नियुक्त न्यायाधीश, ऐसे समय या अतिरिक्त समय के भीतर जांच पूर्ण करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) संबंधित पीठासीन अधिकारी को, ऐसे समय के भीतर, जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(7) जहां यह अभिकथित है कि संबंधित पीठासीन अधिकारी किसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन दक्षतापूर्वक करने में असमर्थ है और उस अभिकथन से इंकार किया जाता है, वहां न्यायाधीश, राष्ट्रपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा पीठासीन अधिकारी की चिकित्सीय परीक्षा का प्रबंध कर सकेंगे और संबंधित पीठासीन अधिकारी, ऐसे समय के भीतर जो न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।

(8) चिकित्सा बोर्ड पीठासीन अधिकारी की आवश्यक समझी जाने वाली चिकित्सीय परीक्षा करेगा और न्यायाधीश को उसमें यह कथन करते हुए कि क्या असमर्थता ऐसी है जिससे पीठासीन अधिकारी अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(9) यदि पीठासीन अधिकारी ऐसी चिकित्सीय परीक्षा करवाने से इंकार करता है जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझी जाए तो

बोर्ड, न्यायाधीश को एक रिपोर्ट, उसमें ये कथन करते हुए प्रस्तुत करेगा कि पीठासीन अधिकारी ने कौन-सी परीक्षा करवाने से इंकार किया है और न्यायाधीश, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह उपधारणा बनाएगा कि पीठासीन अधिकारी ऐसी शारीरिक या मानसिक असमर्थता से पीड़ित है जो परिवाद में अभिकथित है।

(10) न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी के लिखित कथन और चिकित्सीय रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उप-नियम (4) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आरोपों का संशोधन कर सकेगा और ऐसी दशा में, पीठासीन अधिकारी को प्रतिरक्षा का एक नया लिखित कथन प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(11) केन्द्रीय सरकार पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध मामला प्रस्तुत करने के लिए उस सरकार का कोई अधिकारी या कोई अधिवक्ता नियुक्त करेगी।

(12) जहां केन्द्रीय सरकार अपना पक्ष न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कोई अधिवक्ता नियुक्त करती है, वहां संबंधित पीठासीन अधिकारी को भी उसके द्वारा चुने गए अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

6. विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का इन नियमों के अधीन जांचों को लागू होना।—विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 16) के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचों को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विभागीय जांचों को लागू होते हैं।

7. न्यायाधीश की शक्तियां.—न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित प्रक्रिया द्वारा वाध्य नहीं होगा किंतु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और उसे अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी जिसमें उसकी जांच का स्थान और समय का नियत करना भी है।

8. पीठासीन अधिकारी का निलंबन.—नियम 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और उक्त नियम के अनुसार की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रपति, आरोपों की गंभीरता को दृष्टि में रखते हुए उस पीठासीन अधिकारी को, जिसके विरुद्ध कोई शिकायत अन्वेषण या जांच चल रही है, निलंबित कर सकेंगे।

9. निर्वाह भत्ता.—किसी निलंबनाधीन पीठासीन अधिकारी को निर्वाह भत्ते का संदाय, भारत सरकार के समतुल्य पद का और समतुल्य ग्रेड बेतन आहरण करने वाले किसी अधिकारी को तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

10. जांच रिपोर्ट.—अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संपूर्ण मामले पर ऐसे संप्रेषण के साथ जो वह ठीक समझे, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें प्रत्येक मद पर उसके पृथक्-पृथक् निष्कर्ष और उनके लिए कारणों का कथन होगा।

[फा. सं. 14/2/2010-डीआरटी]

विनीता कुमार, आर्धिक सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Financial Services)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2010

**G.S.R. 595(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 15, read with clause (b) of sub-section (2) of Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal (Procedure for Investigation of Misbehaviour or Incapacity of Presiding Officer) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Extent of application.**—These rules shall be applicable to every Presiding Officer of the Debts Recovery Tribunal established under the Act.

**3. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993);

(b) “Judge” means a sitting Judge of the High Court appointed under sub-rule (2) of rule 5 to conduct the inquiry;

(c) “Presiding Officer” means a person appointed as Presiding Officer of a Tribunal under sub-section (1) of Section 4 of the Act;

(d) “Tribunal” means the Debts Recovery Tribunal established under sub-section (1) of Section 4 of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

**4. Committee for investigation of complaints.**—(1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehaviour or incapacity to perform the functions of the office in respect of a Presiding Officer is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with other material as may be available, before a Committee consisting of the following officers to investigate the charges of allegations made in the complaint, namely:—

- (i) Secretary (Coordination and Public Grievances), Cabinet Secretariat —Chairman;
- (ii) Secretary, Ministry of Finance, Department of Financial Services —Member;

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs, —Member, Ministry of Law and Justice

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the High Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

**5. Judge to conduct inquiry.**—(1) If the President is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of a Presiding Officer, he shall make a reference to the Chief Justice of India, requesting him to nominate a Judge of a High Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of the High Court nominated by the Chief Justice of India for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Presiding Officer concerned.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of—

(a) the articles of charges against the Presiding Officer concerned and the statement of imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge appointed under sub-rule (2) shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Presiding Officer concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Presiding Officer concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Presiding Officer by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Presiding Officer concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Presiding Officer as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Presiding Officer unfit to continue in office.

(9) If the Presiding Officer refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Presiding Officer

has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Presiding Officer suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Presiding Officer and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case, the Presiding Officer shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or an advocate to present the case against the Presiding Officer.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Presiding Officer concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

**6. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules.**—The provision of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

**7. Powers of Judge.**—The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his inquiry.

**8. Suspension of Presiding Officer.**—Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President, keeping in view the gravity of charges, may suspend the Presiding Officer against whom a complaint is under investigation or inquiry.

**9. Subsistence allowance.**—The payment of subsistence allowance to the Presiding Officer under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India of equivalent post and drawing an equivalent grade pay.

**10. Inquiry report.**—After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons therefore on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

[F. No. 14/2/2010-DRT]

VINITA KUMAR, Economic Advisor